



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 229]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 1, 1985/ज्येष्ठ 11, 1907

No. 229]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 1, 1985/JYAISTHA 11, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

निर्णार्ण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 मई, 1985

अधिसूचना 1

सा. दा. नि. 472 (अ):—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड नियम, 1985

अध्याय 1

1. नाम—इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड नियम, 1985 है।

2. परिभाषा—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(1) “अधिनियम” से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 अभिप्रेत है ;

(2) “प्ररूप” से इन नियमों में उपवर्णित प्ररूप अभिप्रेत है ;

(3) “निधि” से अधिनियम की धारा 22 के अधीन गठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड निधि अभिप्रेत है ;

(4) “सरकार” से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है ;

(5) “अनुसूची” से इन नियमों से अनुलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(6) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और जो अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं।

अध्याय 2

बोर्ड और समिति का गठन

3. बोर्ड का गठन—बोर्ड का गठन निम्नलिखित 21 सदस्यों से मिलकर होगा:—

(क) निर्माण और आवास का केन्द्रीय मंत्री जो बोर्ड का अध्यक्ष होगा ;

- (ख) हरियाणा का मुख्य मंत्री;
- (ग) राजस्थान का मुख्य मंत्री;
- (घ) उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री;
- (ङ) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक;
- (च) (i) दो सदस्य (जिन्हें हरियाणा राज्य की सिफारिश पर सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा);
- (ii) दो सदस्य (जिन्हें राजस्थान राज्य की सिफारिश पर सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा);
- (iii) दो सदस्य (जिन्हें उत्तर प्रदेश राज्य की सिफारिश पर सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा);
- (iv) दो सदस्य (जिन्हें संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक की सिफारिश पर सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा);
- (छ) (i) सचिव भारत सरकार, निर्माण और आवास मंत्रालय;
- (ii) सचिव, भारत सरकार, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय;
- (iii) एक सदस्य जो ऐसा व्यक्ति होगा जिसे नगर योजना में ज्ञान और अनुभव है, जिसे सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;
- (ज) बोर्ड का एक पूर्णकालिक सदस्य सचिव जिसे भारत सरकार के संयुक्त सचिव की या उसके ऊपर की पंक्ति के अधिकारियों में से सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;
- (झ) चार अन्य सदस्य जिन्हें बोर्ड के कृत्यों और शक्तियों से सुसंगत उनके ज्ञान और अनुभव को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा।

4. बोर्ड के सदस्यों की अवधि—बोर्ड का प्रत्येक सदस्य अपनी सदस्यता सरकार के प्रसाद पर्यन्त धारण करेगा। नियम 3 के खण्ड (च), खण्ड (छ) खण्ड (ज) और खण्ड (झ) के अधीन नामनिर्देशित बोर्ड के सदस्य पद पर तब तक बने रहें जब तक कि सरकार द्वारा नये नामनिर्देशन अधिसूचित नहीं कर दिए जाते हैं या सरकार, किसी अधिसूचना द्वारा किसी सदस्य के नामनिर्देशन को वापस नहीं ले लेती है; परन्तु खण्ड (च) के अधीन नामनिर्देशित सदस्यों की दशा में; उन्हें यथास्थिति, सम्बद्ध भाग लेने वाले राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक की सिफारिश के बिना नहीं हटाया जाएगा।

5. निरहता—कोई भी व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा या उस का सदस्य नहीं बना रहेगा;

- (क) यदि वह विकृतचित्त है और उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है;
- (ख) यदि वह अनुमोचित दिवालिया है;
- (ग) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है;
- (घ) यदि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि के विकास के किसी कामकाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हितबद्ध है।

6. त्यागपत्र—नियम 3 के खण्ड (च), खण्ड (छ) के उपखण्ड (iii) और खण्ड (i) के अधीन नामनिर्देशित कोई सदस्य अपनी सदस्यता में अध्यक्ष को उस आशय की एक सूचना देकर त्यागपत्र दे सकता है और ऐसा त्यागपत्र उप तारीख से जब वह सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है, प्रभावी होगा।

7. रिक्तियां—जहां किसी सदस्य के त्यागपत्र, निरहता, मृत्यु, हटाए जाने या अन्यथा के कारण पद में कोई रिक्ति होती है, वहां वह रिक्ति ऐसी रिक्ति होने के यथाशक्य शीघ्र पश्चात् नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी।

8. सदस्य सचिव की सेवा की शर्तें—सदस्य सचिव के वेतन, भत्ते और उसकी सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो सरकार द्वारा अवधारित की जाए।

9. गैर सरकारी सदस्यों की फीस और भत्ते — (i) बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों को बोर्ड के प्रत्येक दिन के वास्तविक अधिवेशन के लिए ऐसी फीस का संदाय किया जाएगा जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए।

(2) गैर-सरकारी सदस्य ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब वह यथास्थिति बोर्ड या समिति के कार्य में लगे हुए हैं सरकारी सेवकों को लागू नियमों के अधीन पहली श्रेणी के किसी सरकारी सेवक को अनुज्ञेय उच्चतर दर पर यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते प्राप्त करने के भी हकदार होंगे।

10. योजना समिति का गठन—योजना समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर होगा :—

- (क) बोर्ड का सदस्य सचिव जो समिति का अध्यक्ष होगा;
- (ख) संयुक्त सचिव भारत सरकार निर्माण और आवास मंत्रालय। जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से संबंधित कार्य के संबंध में कार्यवाही कर रहा है;
- (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से संबंधित कार्य का भार साधक प्रत्येक भाग लेने वाले राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकार का सचिव;
- (घ) उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण;
- (ङ) मुख्य योजनाकार, नगर और ग्राम योजना संगठन नई दिल्ली; और

- (च) प्रत्येक भाग लेने वाले राज्य का यथास्थिति, निदेशक, नगर और ग्राम योजना या मुख्य नगर योजनाकार।

अध्याय 3

कामकाज का संचालन

11. बोर्ड के अधिवेशन—(1) बोर्ड साधारणतया कामकाज के संचालन के लिए प्रत्येक छह माह में कम से कम एक बार और ऐसे अन्य समयों पर भी अपना अधिवेशन करेगा जिसके लिए अध्यक्ष द्वारा अधिवेशन विशेष रूप से बुलाया जाए।

(2) कोई अधिवेशन अगली या किसी पश्चात्पूर्वी तारीख तक स्थगित किया जा सकेगा और स्थगित अधिवेशन की ऐसी ही रीति में और आगे स्थगित किया जा सकेगा।

12. अधिवेशन और कामकाज की सूचना—साधारण अधिवेशन की कम से कम 15 दिन की सूचना और किसी विशेष अधिवेशन की कम से कम सात दिन की सूचना, जिसमें वह समय और स्थान विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब ऐसे किसी अधिवेशन का आयोजन किया जाना है, सदस्यों को दी जाएगी। साधारण अधिवेशन की दशा में, अधिवेशन में संचालित किए जाने वाला कामकाज अधिवेशन के कम से कम 7 दिन पूर्व सदस्यों को भेजा जाएगा और किसी विशेष अधिवेशन की दशा में संचालित किए जाने वाले कामकाज का उल्लेख अधिवेशन की सूचना के साथ-साथ किया जाएगा।

13. अधिवेशन में विचार-विमर्श के लिये मदों का सम्मिलित किया जाना—(1) ऐसा प्रत्येक सदस्य जो किसी मद को बोर्ड के किसी अधिवेशन की कार्य-सूची में सम्मिलित कराने का इच्छुक है, उसे अधिवेशन की तारीख के कम से कम 15 दिन पूर्व सदस्य-सचिव को भेजेगा।

(2) केवल ऐसी मदों को जो अध्यक्ष द्वारा सम्मिलित किए जाने के लिए अनुमोदित कर दी जाती हैं, कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाएगा।

14. गणपूर्ति—किसी अधिवेशन में कोई भी कामकाज तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम पांच सदस्य उपस्थित न हों। यदि किसी अधिवेशन में गणपूर्ति उपस्थित नहीं है, तो सभापतित्व करने वाला प्राधिकारी, 30 मिनट तक प्रतीक्षा करने के पश्चात् अधिवेशन को उसी दिन या अगले दिन किसी अन्य दिन को ऐसे समय के लिए स्थगित कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसे स्थगन की सूचना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कार्यालय में सूचना-पट्ट पर लगा दी जाएगी और वह कामकाज जो मूल अधिवेशन के समक्ष उस दशा में प्रस्तुत किया जाना था, जब वहां सणपूर्ति होती, स्थगित अधिवेशन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और गणपूर्ति पर विचार किए बिना उसका निपटारा किया जाएगा।

15. सभापतित्व करने वाला अधिकारी (1) अध्यक्ष जब वह उपस्थित होगा, बोर्ड के अधिवेशनों में सभापतित्व करेगा।

(2) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य स्वयं सदस्यों में से अधिवेशन का सभापतित्व करने वाला एक सदस्य निर्वाचित करेंगे।

(3) अध्यक्ष या यथास्थिति उसकी अनुपस्थिति में अधिवेशन का सभापतित्व करने के प्रयोजन के लिये निर्वाचित सदस्य को मत बराबर होने के सभी मामलों में निर्णायक मत का अधिकार होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

16. मतदान—नियमों के अधीन जो अन्यथा उपबंधित हैं उसके सिवाय बोर्ड द्वारा विनिश्चित किए जाने के लिए अपेक्षित सभी विषयों का विनिश्चित उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा।

17. कार्यवाहियों का कार्यवृत्त—उपस्थित सदस्यों के नाम और अधिवेशन की कार्यवाहियां इस प्रयोजन के लिये प्रदान की गई एक पुस्तक में रखी जाएंगी, जिसमें ऐसे अधिवेशन का सभापतित्व करने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह सभी युक्तियुक्त समयों पर किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी।

18. सदस्यों द्वारा ऐसे विषयों पर मतदान न किया जाना जिनमें वे व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध हैं—बोर्ड का कोई सदस्य, बोर्ड के अधिवेशन में लाए गए किसी ऐसे प्रश्न पर मतदान नहीं करेगा या विचार-विमर्श में भाग नहीं लेगा यदि वह प्रश्न ऐसा है जिसमें उसका, इसके आम जनता को साधारणतया लागू होने के अलावा, अपने लिए या अपने संबंधियों के लिए कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धनीय हित है।

19. अधिवेशनों का संचालन—(1) साधारण अधिवेशन :— साधारण अधिवेशनों में कामकाज का संचालन निम्नलिखित क्रम में किया जाएगा :—

(क) पूर्व साधारण अधिवेशन के और ऐसे साधारण अधिवेशन के पश्चात् आयोजित किसी विशेष अधिवेशन के कार्यवृत्त पढ़े जाएंगे और उनकी पुष्टि की जाएगी।

(ख) तब ऐसे पूर्व अधिवेशन में स्थगित कामकाज पर विचार किया जाएगा ;

(ग) कार्य-सूची में सम्मिलित विषयों पर तत्पश्चात् विचार किया जाएगा ;

(घ) किसी अन्य मदों पर भी विचार किया जा सकेगा, यदि सभापतित्व करने वाले अधिकारी ने अनुमति प्रदान कर दी हो।

(2) विशेष अधिवेशन—केवल ऐसे विशेष अधिवेशन में ऐसे कामकाज पर, जिस पर विचार करने के प्रयोजन के लिए विशेष अधिवेशन बुलाया गया है, विचार किया जाएगा।

20. व्यवस्था के प्रश्न—व्यवस्था के सभी प्रश्न सभापतित्व करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसे विचार विमर्श से या उसके बिना विनिश्चित किये जायेंगे जो वह ठीक समझे और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

अध्याय 4

प्रशासन

21. सदस्य-सचिव—सदस्य-सचिव बोर्ड के कार्यालय का मुख्य कार्यपालक होगा और बोर्ड द्वारा नियुक्त सभी अधिकारी और कर्मचारी सदस्य-सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे।

22. आदेशों का अधिप्रमाणीकरण—बोर्ड द्वारा पारित सभी आदेश, दिए गए सभी अनुमोदन, की गई नियुक्ति, सदस्य-सचिव के हस्ताक्षर से संसूचित की जायेंगी।

अध्याय 5

प्रारूप और अन्तिम क्षेत्रीय योजना के प्रकाशन के लिए प्रक्रिया।

23. धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन सूचना का प्रारूप—प्रारूप क्षेत्रीय योजना तैयार होने के यथाशक्य शीघ्र पश्चात्, बोर्ड प्रारूप “क” में एक सूचना प्रकाशित करेगा जिसमें प्रारूप क्षेत्रीय योजना के संबंध में आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे।

24. सूचना की रीति—बोर्ड प्रारूप “क” में एक सूचना दिल्ली से प्रकाशित दो राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्रों में और प्रत्येक भाग लेने वाले राज्य की राज्य राजधानी के दो स्थानीय समाचारपत्रों में प्रकाशित करायेंगा।

25. स्थानीय प्राधिकरण को सूचना—बोर्ड नियम 23 में निर्दिष्ट सूचना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय में भिजवायेगा और ऐसा स्थानीय प्राधिकरण, ऐसी सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप क्षेत्रीय योजना के संबंध में कोई अभ्यावेदन बोर्ड को करेगा।

26. धारा 14 की उपधारा 2 के अधीन सूचना—नियम 23 से 25 के उपबंध अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 2 के अधीन जारी की गई सूचना को, जहां तक हो सके लागू होंगे।

27. धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन सूचना—बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय योजना को अंतिम रूप दिये जाने के यथाशक्यशीघ्र पश्चात्, प्रारूप “ख” में एक सूचना भारत सरकार के राजपत्र में और दिल्ली से प्रकाशित दो राष्ट्रीय समाचारपत्रों में भी तथा भाग लेने वाले राज्यों की प्रत्येक राज्य राजधानी के दो स्थानीय समाचारपत्रों में प्रकाशित की जायेगी जिसमें यह कथन होगा कि अंतिम क्षेत्रीय योजना तैयार कर ली गई है और निरीक्षण के लिये उपलब्ध है।

अध्याय 6

बजट, लेखा और संपरीक्षा

28. बजट प्राक्कलन का प्रारूप—(1) आगामी वर्ष की बाबत बजट जिसमें बोर्ड की प्राक्कलित पावतियां और व्यय दर्शित किये जायेंगे, प्रारूप “ग”, “घ”, “ङ” और “च” में तैयार किया जायेगा और प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर तक सरकार को भेज दिया जायेगा।

(2) ऐसे प्राक्कलनों के साथ चालू वर्ष के लिए पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन भी संलग्न होंगे।

(3) बजट, अनुसूची 1 में दिये गये लेखे शीर्षों पर आधारित होगा।

(4) बजट दो भागों में होगा, एक भाग राजस्व से और दूसरा पूंजी से संबंधित होगा।

29. बोर्ड को बजट प्राक्कलनों का प्रस्तुत किया जाना—(1) नियम 28(1) के अनुसार यथासंकलित बजट प्राक्कलन सदस्य-सचिव द्वारा प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह तक अनुमोदनार्थ बोर्ड के समक्ष रखे जायेंगे।

(2) बोर्ड द्वारा बजट प्राक्कलनों के अनुमोदन के पश्चात् अंतिम बजट प्रस्तावों की पांच प्रतियां जिसमें ऐसे उपान्तरणों का जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित किये गये हैं, समावेश करके, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर की पन्द्रह तक सरकार को भेजी जायेंगी।

30. स्थापन व्यय और नियत आवर्ती प्रभारों का प्राक्कलन—नियत स्थापन पर व्यय का प्राक्कलन जिसके अन्तर्गत अवकाश वेतन और पेंशन अभिदाय तथा किराया, भत्ते आदि के मद्दे नियत मासिक आवर्ती प्रभार भी हैं, किसी प्रकार की कटौती के बिना कुल मंजूर किये गये वेतन का उपबंध करेगा।

31. पुनर्विनियोग और अतिशीघ्र व्यय—ऐसा कोई व्यय जो अनुमोदित बजट प्राक्कलन में किसी उपबंध के अन्तर्गत नहीं आता है या जिसके किसी शीर्ष के अधीन उपबंधित रकम से अधिक होने की संभावना है, बोर्ड द्वारा किसी अन्य शीर्ष के अधीन जिसके अधीन बचतपूर्ण रूप से स्थापित की गई है और उपलब्ध है, पुनर्विनियोग द्वारा कोई उपबंध किए बिना उपगत, नहीं किया जायेगा।

परन्तु बचत का कोई पुनर्विनियोग राजस्व से पूंजी में और पूंजी से राजस्व में अनुज्ञात नहीं होगा।

32. बोर्ड के लेखाओं का खोला जाना और उसकी निधि का प्रवर्तन—बोर्ड की निधि भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में चालू खाते में जिसे “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड” के नाम से खोला जाएगा, रखी जाएगी और वह लेखा बोर्ड के सदस्य सचिव या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रवर्तित किया जाएगा।

33. लेखा और संपरीक्षा—(1) बोर्ड, अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन प्राप्त अनुदानों और उधारों, धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन प्राप्त धन-राशियों और धारा 22 की उपधारा (1) के खंड (ख) और (ग) के अधीन प्राप्त धनराशियों की बाबत बोर्ड के लेखाओं को पृथक् रूप से बनाए रखेगा। लेखाओं के प्ररूप सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(2) बोर्ड के लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में, जो सरकार द्वारा नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के परामर्श से विनिर्दिष्ट किया जाए, होगा।

(3) लेखाओं की भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा संपरीक्षा की जाएगी। तथापि भारत का नियंत्रक-महालेखा परीक्षक अपनी और से संपरीक्षा करने के लिए किसी प्रमुख लेखापरीक्षक की नियुक्त का सुझाव दे सकेगा और तदुपरि ऐसा मुख्य लेखापरीक्षक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों और मार्गदर्शनों के अनुसार लेखाओं की संपरीक्षा करेगा।

34. सहायता अनुदान—बोर्ड में भाग न वाली राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या ऐसी राज्य सरकारों को जिनमें प्रत्याकर्षण क्षेत्र है और स्थानीय प्राधिकरण नगर विकास प्राधिकरणों, आवास बोर्डों और यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या संबंधित अन्य राज्य सरकार के ऐसे अन्य राज्य प्राधिकरणों को उप-क्षेत्रीय योजनाओं और परियोजनाओं प्लानों के कार्यान्वयन के लिए या प्रत्याकर्षण क्षेत्र के विकास के लिए सहायता अनुदान मंजूर कर सकेगा।

35. सहायता अनुदान मंजूर करने के लिए प्रक्रिया—(1) (क) जब तक कि किसी मामले में बोर्ड अन्यथा निदेशित नहीं करता है, अनुदान मंजूर करने वाला प्रत्येक आदेश यह उपदिष्ट करेगा कि क्या वह आवर्ती या अनावर्ती प्रकार का है और स्पष्ट रूप से उस उद्देश्य को विनिर्दिष्ट करेगा जिसके लिए वह दिया गया है और उस अनुदान के साथ लगाई गई शर्तें यदि कोई हों, का भी विनिर्देश किया जाएगा। विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए अनावर्ती अनुदानों की दशा में आदेश उस समय-सीमा को भी विनिर्दिष्ट करेगा जिसके अंतर्गत अनुदान या उसकी प्रत्येक किश्त खर्च की जानी है।

(ख) सहायता अनुदान के संदाय के लिए आदेश इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि किसी विनिर्दिष्ट राशि के संदाय के लिए उसमें विनिर्दिष्ट निदेश हो और वह अनुदान सहायता अनुदान के प्रस्ताव का अनुमोदन करने वाले आदेश से सुभिन्न होना चाहिए।

2(क) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान केवल उतना अनुदान संदत्त किया जाएगा जितना उस वर्ष के दौरान खर्च किया जाना संभाव्य है। विनिर्दिष्ट निर्माण या सेवाओं जैसे

भवनों, जल प्रदाय स्कीमों और वैसे ही अन्य कार्यों के लिए अनुदानों की दशा में संदाय कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार प्राधिकृत किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रकम अपेक्षाओं के अग्रिम रूप में नहीं निकाली जाती है। इन अनुदानों के संदाय के लिए मार्च के मास में भीड़ से वचा जाना चाहिए।

(ख) जहां सहायता अनुदान के अंतर्गत एक समय में किया जाने वाला संदाय अंतर्वर्तित हो वहां वह जहां तक संभव हो दिसम्बर के अंत से पूर्व संदाय कर दिया जाना चाहिए। किसी अन्य दशा में, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में ऐसे अनुदानों के संदाय के लिए भीड़ से वचा जाना चाहिए।

(3) किसी स्थानीय प्राधिकरण, नगर विकास प्राधिकरण, आवास बोर्ड या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के ऐसे अन्य प्राधिकरणों को अनुदान संदत्त किए जाने से पूर्व बोर्ड, संबंधित प्राधिकरण के लेखाओं के संपरीक्षित विवरणों की निम्नलिखित प्रतियां यह देखने के लिए अभिप्राप्त करेगा कि सहायता अनुदान प्राप्तकर्ता की वित्तीय स्थिति द्वारा न्यायोचित है और यह सुनिश्चित करेगा कि पूर्व अनुदान, यदि कोई हो, का खर्च उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया गया था जिनके लिए वे आशयित थे:—

- (i) पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए प्राधिकरण की प्राप्ति और संदाय लेखे;
- (ii) पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए प्राधिकरण के आय और व्यय लेखे; और
- (iii) पूर्ण वित्तीय वर्ष के अंत में प्राधिकरण के लिए तुलन-पत्र, यदि कोई है।

36. उपयोग का प्रमाणपत्र—ऐसे मामलों में जिनमें स्थानीय प्राधिकरणों, नगर विकास प्राधिकरणों, आवास बोर्डों और राज्य सरकारों और संघ-राज्यक्षेत्र प्रशासनों के ऐसे अन्य प्राधिकरणों को मंजूर किए गए अनुदानों के उपयोग के साथ व्यय के विशेष उद्देश्यों के विनिर्देश के रूप में या उस समय के रूप में जिसके भीतर धन खर्च किया जाना चाहिए या अन्यथा कोई शर्त लगा दी गई है, राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन बोर्ड को जहां आवश्यक हो, अनुदान के साथ लगी शर्तों का पालन प्रमाणित करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होगा।

37. सहायता अनुदान की शर्तें—(1) जब तक कि बोर्ड द्वारा अन्यथा आदेश न किया जाए, किसी विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए दिया गया प्रत्येक अनुदान निम्नलिखित विवक्षित शर्तों के अधीन है:—

- (i) यह कि अनुदान एक युक्तियुक्त समय के भीतर उद्देश्य पर खर्च किया जाएगा यदि उसके लिए बोर्ड द्वारा कोई समय-सीमा नियत नहीं की गई है;
- (ii) यह कि रकम का कोई भाग जो उस उद्देश्य पर व्यय के लिए अंततः अपेक्षित नहीं है, बोर्ड को सम्यक् रूप से वापस लौटा दिया जाएगा।

(2) बोर्ड, उस रीति की बाबत जिसमें प्राप्तिकर्ता-निकाय के क्रियाकलापों का प्रबन्ध किया जाता है और अनुदानों का उपयोग किया जाता है, अपना समाधान करने के लिए, बोर्ड से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा करने की अपेक्षा कर सकेगा।

38. उधार—बोर्ड, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरणों, नगर विकास प्राधिकरण, आवास बोर्डों या यथास्थिति, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र के ऐसे अन्य प्राधिकरणों को जो उप-क्षेत्रीय योजनाओं, परियोजना प्लानों को कार्यान्वित कर रहे हैं या किसी प्रत्याकर्षण क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, उधार मंजूर कर सकेगा।

39. उधार की शर्तें (1) उधारों को सभी मंजूरीयों में ऐसे निबन्धन और शर्तें जिसके अंतर्गत पुनर्संदाय और ब्याज के संदाय के निबन्धन और शर्तें भी हैं, विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(2) उधार लेने वालों से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वे उनको दिए गए उधारों के लिए तय किए गए निबन्धनों का सर्वदा पालन करेंगे। उनके पक्ष में किसी निबन्धन का उपातरण केवल विशेष कारणों से बाद में किया जा सकता है।

40. ब्याज की संगणना—(1) ब्याज ऐसी दर पर जो किसी विशेष उधार के लिए या संबंधित वर्ष के किसी उधार के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रसारित की जाएगी और सरकार द्वारा समय-समय पर विहित ब्याज की दर बोर्ड द्वारा आवश्यक रूप से अपनाई जाएगी।

(2) उधार पर ब्याज संदाय के दिन के लिए लगूना न कि पुनर्संदाय के दिन के लिए। किसी पूर्ण वर्ष की अपेक्षा में संक्षिप्त कालावधि के लिए, ब्याज निम्न प्रकार संगणित किया जाएगा:—

दिनों की संख्या ब्याज की वार्षिक दर

365

जब तक कि संगणना की कोई अन्य पद्धति किसी विशेष मामले या मामलों के वर्ग में बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट न की जाए।

41. उधार विषयक करार स्थानीय प्राधिकरणों, नगर विकास प्राधिकरणों, आवास बोर्डों और राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से भिन्न ऐसे अन्य प्राधिकरणों को उधारों की दशा में एक उधार विषयक करार जिसमें सभी निबन्धन और शर्तें विनिर्दिष्ट की जाएगी, निष्पादित किया जाएगा। ऐसे सभी करारों में अनिवार्य रूप से एक खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा जो बोर्ड को किसी लेखा वर्ष से संबंधित आवेदकों के लेखाओं को किसी भी समय मंगाने के लिए समर्थ करता हो और यदि आवश्यक हो तो आवेदकों

की लेखा वहीनों को निरीक्षण के लिए इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त करने की शक्ति हो।

42. उधारों के लिए प्राप्तिभूति—स्थानीय प्राधिकरणों, नगर विकास प्राधिकरणों, आवास बोर्डों और राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से भिन्न ऐसे अन्य प्राधिकरणों को उधार केवल समुचित प्रतिभूति के विरुद्ध ही मंजूर किए जाएंगे। ली जान वाली प्रतिभूति साधारणतया उधार की रकम कम से कम 33—1/2 प्रतिशत अधिक होगी; परन्तु बोर्ड प्रतिभूति के बदले राज्य की प्रत्याभूति भी प्रतिग्रहीत कर सकेगा।

43. राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित किया जाना (1) उधार के संदाय के लिए आदेश इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि उसमें विनिर्दिष्ट धनराशि के संदाय के लिए विनिर्दिष्ट निदेश हों और वह उधार के किसी प्रस्ताव का अनुमोदन करने वाले आदेशों से भिन्न होना चाहिए।

(2) ऐसे मामलों में जहां उधार प्राधिकरणों जैसे स्थानीय प्राधिकरणों, नगर विकास प्राधिकरणों, आवास बोर्डों और राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से भिन्न ऐसे अन्य प्राधिकरणों को उधार मंजूर किया जाता है जिनमें विशेष उद्देश्य के विनिर्देश के रूप में या उस समय के रूप में जिसके भीतर धन खर्च किया जाना चाहिए या अन्यथा के रूप में उधार के उपयोग के लिए शर्त लगा दी गई है, वहां राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन उधार के साथ लगी शर्तों के पालन के लिए बोर्ड को प्रमाणित करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होंगे।

44. किस्तों में संदाय और अधिस्थगन—जब उधार किस्तों में निर्भूत किया जाता है तो इस प्रकार ली गई उधार को प्रत्येक किस्त को मूल के प्रतिसंदाय और उस पर ब्याज के संदाय के प्रयोजनों के लिए पृथक् उधार के रूप में माना जाएगा सिवाय वहां के जहां किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ली गई पूर्व किस्तों को इस प्रयोजनार्थ उस विशेष वित्तीय वर्ष के अन्त में एकल उधार के रूप में समेकित किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया है। पश्चात्तवर्ती मामले में, विभिन्न उधार की किस्तों पर प्रत्येक किस्त प्राप्त करने की तारीख से लेकर उनके समेकन की तारीख तक विनिर्दिष्ट दर पर साधारण ब्याज उधार लेने वाले द्वारा प्रत्येक रूप से संदेय होगा। यथास्थिति प्रत्येक उधार या समेकित उधार का प्रतिसंदाय और उस पर ब्याज के संदाय को प्रतिवर्ष उधार लेने वाले द्वारा उधार लेने या उसके समेकन को वापिक तारीख को या उससे पूर्व उतनी किस्तों में जितनी बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, व्यवस्था की जाएगी। बोर्ड, उचित मामलों में मूल के प्रतिसंदाय के लिए अधिस्थगन को अनुज्ञा दे सकता है न कि ब्याज के संदाय के लिए यदि यह प्रतीत हो कि किसी उधार की अन्तिम किस्त लेने में ऋणों को ओर से सम्यक् बिलंब हुआ है तो बोर्ड किसी भी समय ऋणों को गन्द घोषित कर सकता और शुरू में

पूँजी के प्रतिसंदाय का आदेश दे सकता है। बोर्ड के लेखाओं का भारसाधक अधिकारी हुए ऐसे किसी विलंब को बोर्ड की दृष्टि में लाएगा जिसके बारे में उसे यह प्रतीत होता हो कि उसे इस उपचार की अपेक्षा है और वह यह कार्य-वाई करेगा कि क्या किस्तों के लेने के लिए कोई तारीख नियत की गई है या नहीं।

45. संदाय में व्यक्तिगत—(1) सभी मामलों में उधार मंजूरीयों और स्थानीय प्राधिकरणों, नगर विकास प्राधिकरणों, आवास बोर्डों और ऐसे अन्य प्राधिकरणों की दशा में करार के अन्तर्गत अतिशोध्य ब्याज या मूल और ब्याज की किस्तों पर शास्तिक ब्याज के उद्ग्रहण का अनिवार्य रूप से एक उपबंध सम्मिलित किया जाना चाहिये। स्थानीय प्राधिकरणों, नगर विकास प्राधिकरणों, आवास बोर्डों और राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के ऐसे अन्य बोर्डों की दशा में उधार मंजूरीयों और करारों के अन्तर्गत ब्याज की अनिवार्य रूप में उच्चतर दर अनुबंधित की जानी चाहिये और नियमित संदायों की दशा में ब्याज की निम्नतर दर का उपबंध किया जाना चाहिये। यथास्थिति, ब्याज की शास्तिक या उच्चतर दर बोर्ड के विशेष आदेशों के अधीन के सिवाय, बोर्ड द्वारा अग्रिम दिये गये उधार के लिए समय-समय पर विनिर्दिष्ट ब्याज की सामान्य दर से अधिक 2 1/2 प्रतिशत प्रति वर्ष से कम नहीं होगी।

(2) उधार पर ब्याज के संदाय में या मूल के प्रति-संदाय में हुए किसी व्यक्तिगत की बोर्ड के लेखाओं के भारसाधक अधिकारी द्वारा तुरन्त रिपोर्ट दी जायेगी।

46. लेखे और नियंत्रण—ऐसे साधारण और विनिर्दिष्ट निदेशों के अधीन रहते हुए जो नियंत्रक और महा-लेखा-परीक्षक द्वारा दिये जायें, बोर्ड द्वारा दिये गये अनुदानों और उधारों के विस्तृत लेखे, लेखाओं के भारसाधक अधिकारी द्वारा बनाये रखे जायेंगे जो उनकी वसूली पर भी निगरानी रखेगा और यह देखेगा कि हर एक उधार के साथ लगाई गई शर्तों का पालन किया गया है।

47. उधारों और अग्रिमों का वार्षिक विवरण—(1) बोर्ड के लेखाओं का भारसाधक अधिकारी बोर्ड को एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें “बोर्ड द्वारा उधार और अग्रिम” शीर्षक के अधीन उसकी लेखा वहीयों में दर्ज बकाया उधारों के व्यय दर्शित किये जायेंगे।

(2) बोर्ड का भारसाधक अधिकारी बोर्ड को एक वार्षिक विवरण भी प्रस्तुत करेगा जिसमें “बोर्ड द्वारा प्राप्त उधार और अग्रिम” शीर्षक के अधीन बोर्ड द्वारा प्राप्त बकाया उधारों के व्यय दर्शित किये जायेंगे। विवरण प्रारूप “ज” में प्रस्तुत किया जायेगा।

अध्याय-7

प्रकीर्ण

48. वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने का प्रारूप और समय—पिछली समाप्त वर्ष की बाबत वार्षिक रिपोर्ट में जिसमें पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड के क्रियाकलापों का सही और पूर्ण लेखा जोखा होगा, अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी और वह प्रति वर्ष 15 मई तक सरकार को प्रस्तुत की जायेंगी।

[सं० के०-14011/15/84-एन०सी०आर०]

आर० एल० प्रदीप, संयुक्त सचिव

प्रारूप क

(नियम 23 देखिए)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड नियम, 1985 के नियम 23 के साथ पठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन सूचना दी जाती है कि :—

(1) (क) क्षेत्रीय योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है; और

(ख) उसकी एक प्रति (-----) पर स्थित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कार्यालय में सभी कार्य दिवसों को 11 बजे पूर्वान्ह से 3 बजे अपराह्न तक इसमें इसके पश्चात् पैरा 3 में वर्णित तारीख तक निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगी।

(2) प्रारूप क्षेत्रीय योजना के लिये आक्षेप सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं।

(3) आक्षेप और सुझाव (-----) पर स्थित सदस्य-सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को-----तारीख से पूर्व लिखित रूप में भेजे जा सकेंगे।

आक्षेप या सुझाव देने वाले किसी व्यक्ति को अपना नाम और पता भी देना चाहिये।

स्थान : नई दिल्ली

सदस्य सचिव,

तारीख :

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

प्ररूप ख
(नियम 27 देखिए)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड नियम, 1985 के नियम 27 के साथ पठित राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के नियम 13 के उपनियम (1) के अधीन सूचना दी जाती है कि:—

(1) (क) अन्तिम क्षेत्रीय योजना तैयार हो गई है, और

(ख) उसकी एक प्रति (-----) पर स्थित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कार्यालय में सभी कार्य दिवसों को 11 बजे पूर्वाह्न से बजे अपराह्न तक निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगी।

स्थान : नई दिल्ली

सदस्य सचिव,

तारीख :

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बो

प्ररूप ग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

वर्ष 19 के लिये विस्तृत बजट प्राक्कलन

प्रशासन (व्यय)

(नियम 28 देखिए)

वास्तविक व्यय की तुलना में पुनरीक्षित प्राक्कलन 19—और बजट प्राक्कलन 19—दर्शित करने वाला विवरण

वेतन, यात्रा भत्ता कार्यालय व्यय आदि जैसे व्यय के उद्देश्य	वास्तविक वर्ष के लिये			मंजूर किये गये बजट अनुदान	अन्तिम वास्तविक सात मास 19—	चालू वर्ष 19— के पहले पांच मास वास्तविक	वर्ष 19— के शेष सात मासों के लिये अनु- मानित व्यय	वर्ष 19— के लिये पुनरीक्षित प्राक्कलन	वर्ष 19— के लिये प्रस्तावित बजट प्राक्कलन	स्तंभ 5, स्तंभ 9 और 9 और 10 के बीच फेर-फार के कारण।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्ररूप घ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड स्थापन

वर्ष 19— 19— के लिये अधिकारियों और स्थापनों के वेतन के लिये प्रस्तावित उपग्रंथ के व्ययों का विवरण।

(नियम 28 देखिए)

नाम और पदाभिधान	प्राक्कलन प्ररूप के पृष्ठ का निर्देश	पद का मंजूर किया गया वेतन	स्तंभ 3(ग) में दूर पर वर्ष के लिये उपग्रंथित रकम	वर्ष के भीतर देय होने वाली वेतन वृद्धि	वर्ष के लिये कुल उपग्रंथ अर्थात् स्तंभ 4 और 4(ग) का योग	टिप्पणी
		न्यूनतम/अधिकतम-आगामी वर्ष 1 अप्रैल को सम्बन्धित व्यक्ति को देय वास्तविक वेतन		वेतन वृद्धि की तारीख (क)	वेतन वृद्धि की दर (ख)	वर्ष के वेतन वृद्धि को रकम (ग)
(क)	(ख)	(ग)				
1	2	3	4	5	6	7

प्ररूप ड

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

अभिहित नामावली

(नियम 28 देखिए)

आर-ई 19—19/बी-ई 19—19

नाम और पदाभिधान	वेतन	महंगाई भत्ता	नगर प्रति- करात्मक भत्ता	मकान किराया भत्ता	अतिकाल भत्ता	बच्चों का शैक्षिक भत्ता	अवकाश यात्रा रियायत	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्ररूप च

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

नामित रोल्स के उद्धरण

(नियम 28 देखिए)

1- 3- 19 को वास्तविक मंजूर कौं गई संख्या	पदों की विशिष्टियां	19- 19- के लिए मंजूर किया गया बजट अनुदान 19- 19	पुनरीक्षित प्राक्कलन 19	बजट प्राक्कलन 19 - 19	मंजूर किए गए बजट, अनुदान, पुनरीक्षित प्राक्कलन और बजट प्राक्कलन के बीच अंतर के लिए स्पष्टीकरण			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- 1- अधिकारी
(क) भरे गए पद
(ख) रिक्त पद
कुल I अधिकारी
2- II अस्थापन
(क) भरे गए पद
(ख) रिक्त पद
3- वर्ग- 4
(क) भरे गए पद
(ख) रिक्त पद
कुल III वर्ग IV

कुल योग : 1, 2 और 3

प्ररूप छ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

बोर्ड द्वारा मंजूर किए गए उधार/अग्रिमों का विवरण

वित्तीय वर्ष 19

[नियम 47 (1) देखिए]

उधार/मंजूर अग्रिम किए गए दर प्राप्त उधार/ करने अग्रिम वाण की रकम व्यक्ति/ पक्षकार का नाम	व्याज की उधार/अग्रिम को प्राधिकृत करने वाले आदेश की संख्या और तारीख	पिछले वर्ष से अति- शेष	इस वर्ष कुल अग्रिम दी गई रकम	मूल का प्रतिसंदाय				व्याज का संदाय					
				वर्ष के दौरान प्रति- संदाय की किस्तों और पूर्विक वर्षों के संबंध में शोध किरनों की वकाया यदि कोई है, (अंकों को वर्ष वार दशित कीजिए)	वर्ष के दौरान प्रति- संदाय की मंदत मूल की रकम	मूल के प्रति- संदाय में व्यतिक्रम की रकम (स्तंभ 8 स्तंभ 9) (अंक वर्ष वार दशित कीजिए)	वर्ष के अंत में उधार/ अग्रिम का अतिशेष (स्तंभ 7 स्तंभ 9)	पुनर्विलोकन के अधीन वर्ष के लिए और उम तक शोध व्याज की रकम	वर्ष के दौरान प्राप्त और राजस्व में जमा व्याज की रकम	असंदत्त व्याज का अति- शेष			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

पाद टिप्पण

1- वर्ष के दौरान समेकित उधार की रकम स्तंभ 6 में भी उपदर्शित की जाएगी।

2- वर्ष के दौरान व्यष्टिक किस्त की बाबत प्राप्त और संदत्त माधारग व्याज स्तंभ 13 में विगिष्ट किस्तों के मामले उपदर्शित किया जा सकेगा।

प्ररूप ज

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

बोर्ड द्वारा प्राप्त उधार/अग्रिमों का विवरण—वित्तीय वर्ष 19-----

[नियम 47 (2) देखिए]

उधार/अग्रिम प्राप्त करने वाले व्यक्ति/पक्षकार का नाम	प्राप्त उधार/अग्रिम की रकम	व्याज की दर	उधार/अग्रिम को प्राधिकृत करने वाले आदेशों की संख्या और तारीख	पिछले वर्ष का अति-शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त रकम	कुल	मूल का संदाय				व्याज का संदाय			
							वर्ष के दौरान प्रतिसंदाय की किस्तों और पूर्विक वर्षों, यदि कोई हों, से सम्बन्धित शोध किस्तों की वकाया (अंक वर्ष वार दशित कीजिए)	वर्ष के दौरान प्रति-संदत्त मूल की रकम	मूल के प्रति-संदाय में व्यतिक्रम की स्तंभ 9)	वर्ष के अंत में उधार/अग्रिम का अतिशेष (स्तंभ 7 स्तंभ 9)	पुनर्विलोकन के अधीन वर्ष के लिए और उस तक शोध व्याज की रकम	वर्ष के दौरान संदत्त और राजस्व में जमा की गई व्याज की रकम	असंदत्त व्याज का अति-शेष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

अनुसूची--I

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

बजट और लेखा शीर्ष

[नियम 28 देखिए]

प्रशासन

लेखा शीर्ष (व्यय)

1. वेतन
2. मजदूरी
3. यात्रा व्यय
4. कार्यालय व्यय
 - (क) फर्नीचर
 - (ख) डाक महसूल
 - (ग) कार्यालय भर्ष न/उपस्कर
 - (घ) वदियां
 - (ङ) श्र.पम/श्र.त मौसम प्रभार
 - (च) दूरभाष
 - (छ) विद्युत और जल प्रभार
 - (ज) लेखन सामग्री
 - (झ) मुद्रण
 - (ञ) स्टाफ कार और अन्य यान
 - (ट) अन्य मदें।
5. फीस और मानदेय
6. वृत्तिक और विशेष सेवाओं के लिए संदाय
7. किराया, दरें और कर/स्वामिस्व
8. प्रकाशन
9. विज्ञान, विक्रय और प्रचारव्यय
10. उधार/सहायता अनुदान/अभिदाय/सहायकी
11. अतिथि व्यय, सत्कार भत्ता आदि
12. अपलिखित करना/हानियां
13. उचंचत
14. अन्य प्रभार (अवशिष्ट शीर्ष, इसके अन्तर्गत पुरस्कार और इनाम भी सम्मिलित होंगे)।

लेखा शीर्ष (प्राप्तियां)

1. केन्द्रीय सरकार द्वारा संदाय
2. फीस
3. जुमाना और अन्य प्राप्तियां

अनुसूची--2

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप

(नियम 48 देखिए)

वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट

अप्रैल 19-- मार्च 19--

1. प्राक्कथन
2. बोर्ड का गठन जिसके अन्तर्गत उसमें किए गए परिवर्तन भी हैं।
3. बोर्ड के अधिवेशन
4. योजना समिति का गठन जिसके अन्तर्गत उसमें किए गए परिवर्तन भी हैं।
5. योजना समिति के अधिवेशन
6. विभिन्न उपक्षेत्रों में क्रियाकलाप के व्यीरे।
7. धारा 8 की उपधारा (च) के अधीन चुने हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर है--नगरीय क्षेत्रों में क्रियाकलाप के व्यीरे।

MINISTRY OF WORKS & HOUSING

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 1985

G.S.R. 472 (E).—In exercise of the powers conferred by section 36 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

THE NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD RULES, 1985

Chapter I

1. Title :—These rules may be called the National Capital Region Planning Board Rules, 1985.

2. Definitions:—In these rules, unless the context otherwise requires :—

- (1) “Act” means the National Capital Region Planning Board Act, 1985;
- (2) “Form” means a form set forth in these rules;
- (3) “Fund” means the National Capital Region Planning Board Fund constituted under section 22 of the Act;
- (4) “Government” means the Central Government;
- (5) “Schedule” means a schedule appended to these rules;
- (6) Words and expressions used in the rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

Chapter II

CONSTITUTION OF THE BOARD AND THE COMMITTEE

3. Constitution of the Board:—The Board shall consist of the following 21 members:—

- (a) the Union Minister of Works and Housing who shall be the Chairman of the Board;
- (b) the Chief Minister of Haryana;
- (c) the Chief Minister of Rajasthan;
- (d) the Chief Minister of Uttar Pradesh;
- (e) the Administrator of the Union Territory of Delhi;
- (f) (i) two members (to be nominated by the Government on the recommendation of the State of Haryana);

(ii) two members (to be nominated by the Government on the recommendation of the State of Rajasthan);

(iii) two members (to be nominated by the Government on the recommendation of the State of Uttar Pradesh);

(iv) two members (to be nominated by the Government on the recommendation of the Administrator of the Union Territory);

(g) (i) Secretary to the Government of India in the Ministry of Works and Housing;

(ii) Secretary to the Government of India, Department of Expenditure, Ministry of Finance;

(iii) one member who shall be a person having knowledge and experience in town planning, to be nominated by the Government;

(h) a full-time Member-Secretary of the Board to be nominated by the Government from amongst officers of, or above, the rank of a Joint Secretary to the Government of India;

(i) four other members to be nominated by the Government having regard to their knowledge and experience relevant to the functions and powers of the Board.

4. Terms of the Members of the Board:—Every member of the Board shall hold his membership at the pleasure of the Government. The members of the Board nominated under clause (f), clause (g), clause (h) and clause (i) of rule 3 shall continue in office unless fresh nominations are notified by the Government or the Government, by a notification withdraws the nomination of any member; provided that in the case of members nominated under clause (f) shall not be removed except on the recommendation of the participating State concerned, or as the case may be, the Administrator of the Union Territory.

5. Disqualification:—No person shall be appointed as, or continue to be a member of the Board :

- (a) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court;
- (b) if he is an undischarged insolvent ;
- (c) if he is not a citizen of India;
- (d) if he is interested, directly or indirectly in any business of development of land in the National Capital Region;

6. Resignation :—Any member nominated under clause (f), sub-clause (iii) of clause (g) and clause (i) of rule 3, may resign his membership by giving a

notice to that effect to the Chairman and such resignation shall take effect from the date of it is accepted by the Government.

7. Vacancies :—Where a vacancy occurs in the office of a member by reason of resignation, disqualification, death, removal or otherwise, the vacancy shall be filled as soon as may be after the occurrence of such vacancy, by nomination.

8. Conditions of service of the Member-Secretary :—The salaries, allowances and conditions of service of the Member-Secretary shall be such as may be determined by the Government.

9. Fees and Allowances to non-official members:—
(1) Non-Official members of the Board shall be paid such fee as may be determined by the Board, from time to time, for each day of the actual meeting of the Board.

(2) Non-Official members shall also be entitled to draw travelling allowance and other allowances for each day he is engaged in the work of the Board or the Committee, as the case may be, at the highest rate admissible to a Government servant of the first grade under the rules applicable to the Government servants.

10. Constitution of the Planning Committee:—The Planning Committee shall consist of following members :—

- (a) the Member-Secretary to the Board who shall be chairman of the Committee;
- (b) the Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Works and Housing dealing with the work relating to the National Capital Region Planning Board;
- (c) Secretary to the Government of each participating State and the Union Territory in charge of the work relating to the National Capital Region Planning Board;
- (d) the Vice Chairman, Delhi Development Authority;
- (e) the Chief Planner, Town and Country Planning Organisation, New Delhi ; and
- (f) the Director, Town and Country Planning or the Chief Town Planner, as the case may be, of each participating State.

Chapter III

CONDUCT OF BUSINESS

11. (1) Meetings of the Board:—The Board shall ordinarily meet at least once in every six months for the transaction of business and also at such other

times as a meeting may be specially convened by the Chairman.

(2) Any meeting may be adjourned until the next or any subsequent date and an adjourned meeting may be further adjourned in like manner.

12. Notice of meeting and Business:—Not less than 15 days' notice of an ordinary meeting and not less than 7 days' notice of a special meeting specifying the time and place at which such a meeting is to be held shall be given to the members. In case of an ordinary meeting, the business to be transacted in the meeting will be sent to the members at least seven days before the meeting and in the case of a special meeting the business to be transacted will be mentioned along with the notice for the meeting.

13. Inclusion of items for discussion in the meeting:—(1) Every member who wishes to have any item to be included in the Agenda in a meeting of the Board shall send the same to the Member-Secretary at least 15 days before the date of the meeting.

(2) Only those items which are approved by the Chairman for inclusion will be included in the Agenda.

14. Quorum:—No business shall be transacted at any meeting unless at least five members are present. If at any meeting quorum is not present, the presiding authority shall, after waiting for thirty minutes, adjourn the meeting to such hour on the same or following day or some other day as he may think fit and a notice of such adjournment shall be affixed on the notice board in the office of the National Capital Region Planning Board and the business which was to have been brought before the original meeting had there been a quorum shall be brought before the adjourned meeting and may be disposed of irrespective of the quorum.

15. Presiding Officer:—(1) The Chairman, when present, shall preside over the meetings of the Board.

(2) In the absence of the Chairman, the members present shall elect from amongst themselves a member to preside over the meeting.

(3) The Chairman or in his absence the member elected for the purpose of presiding over the meeting, as the case may be, shall have and exercise the right of a casting vote in all cases of equality of votes.

16. Voting:—Save as otherwise provided under the rules, all matters required to be decided by the Board shall be decided by the majority of votes of the members present.

17. Minutes of proceedings:—The names of the members present and the proceedings of the meeting shall be kept in a book to be provided for this purpose

which shall be signed by the Presiding Officer of such a meeting and shall at all reasonable times be open to inspection by any member.

18. Members not to vote on matters in which they are personally interested.—No member of the Board shall vote or take part in the discussions on any questions coming up for consideration at the meeting of the Board if the question is one in which, apart from its general application to the public, he has any direct or indirect pecuniary interest for himself or his relatives.

19. Conduct of meetings.—(1) Ordinary meetings:—At an ordinary meeting, business shall be conducted in the following order:—

- (a) The minutes of the previous ordinary meeting and any special meeting held after such ordinary meeting shall be read and confirmed;
- (b) the business postponed at the previous meeting shall then be considered;
- (c) subjects included in the agenda shall thereafter be considered;
- (d) any other items may also be considered if permitted by the Presiding Officer.

(2) Special meetings.—At a special meeting only the business for the purpose of considering which the special meeting has been called shall be considered.

20. Points of order.—All points of order shall be decided by the Presiding Officer with or without discussions as he may deem fit and his decision shall be final.

CHAPTER IV

ADMINISTRATION

21. Member-Secretary.—The Member-Secretary shall be the Chief Executive of the office of the Board and all the officers and employees appointed by the Board shall be under the administrative control of the Member-Secretary.

22. Authentication of orders.—All orders passed approvals given and appointments made by the Board shall be conveyed under the signature of the Member-Secretary.

CHAPTER V

PROCEDURE FOR PUBLICATION OF DRAFT AND FINAL REGIONAL PLAN

23. Form of notice under sub-section 1 of section 12.—As soon as may be after the draft regional plan has been prepared, the Board shall publish a notice

in Form 'A' inviting objections and suggestions with respect to the draft Regional Plan.

24. Manner of notice.—The Board shall cause the notice in Form 'A' to be published in two national daily newspapers published from Delhi and two local newspapers each from the State Capital of each participating State.

25. Notice to local authority.—The Board shall also cause the notice referred to in rule 23 to be sent to the office of every local authority within the National Capital Region and such local authority may within a period of thirty days from the date of such notice, make any representation with respect to the draft Regional Plan to the Board.

26. Notice under sub-section (2) of section 14.—The provisions of rules 23 to 25 shall apply, as far as may be, to the notice issued under sub-section 2 of section 14 of the Act.

27. Notice under sub-section (1) of section 13.—As soon as may be, after the Regional Plan has been finalised by the Board, a notice in Form 'B' shall be published in the Official Gazette of the Government of India and also two national newspapers published from Delhi and two local newspapers each from the State Capital of the participating States, stating that the final Regional Plan has been prepared and is available for inspection.

CHAPTER VI

BUDGET, ACCOUNTS AND AUDIT

28. Form of budget estimates.—(1) The budget in respect of the year next ensuing showing the estimated receipts and expenditure of the Board shall be prepared in Forms 'C', 'D', 'E' and 'F' and forwarded to the Government by the 15th October each year.

(2) Such estimates shall be accompanied by the revised budget estimates for the current year.

(3) The budget shall be based on the account heads given in Schedule I.

(4) The budget shall be in two parts; one part relating to Revenue and the other to Capital.

29. Submission of budget estimates to the Board.—(1) The budget estimates as compiled in accordance with rule 28(1) shall be placed by the Member-Secretary before the Board by the first week of October each year for approval.

(2) After approval of the budget estimates by the Board, five copies of the final budget proposals incorporating therein such modifications as have been decided upon by the Board shall be forwarded to the Government by the 15th of October each Year.

30. Estimates of establishment expenditure and fixed recurring charges.—The estimates of expenditure of fixed establishment which will also include leave salary and pension contributions as well as fixed monthly recurring charges on account of rent allowances, etc., shall provide for the gross sanctioned pay without deductions of any kind.

31. Reappropriations and emergent expenditure.—No expenditure which is not covered by a provision in the approved budget estimates or which is likely to be in excess over the amount provided under any Head shall be incurred by the Board without provision being made by reappropriation from some other Head under which savings are firmly established and available:

Provided that no reappropriation of savings shall be permitted from revenue to capital and vice versa.

32. Opening of an account and operation of fund of the Board.—The Fund of the Board shall be kept in a current account with any branch of the State Bank of India to be opened in the name of "The National Capital Region Planning Board" and shall be operated by the Member-Secretary of the Board or any officer authorised by him in this behalf.

33. Accounts & Audit.—(1) The Board shall maintain the accounts of the Board separately with regard to the grants and loans received under sub-section (1) of the section 21, sums received under sub-section (2) of section 21 and sums received under clauses (b) and (c) of sub-section (1) of section 22 of the Act. The forms of accounts will be specified by the Government in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

(2) The annual statement of accounts of the Board shall be in such forms as may be specified by the Government in consultation with the Comptroller and Auditor General.

(3) The accounts shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India. However, Comptroller and Auditor General of India may suggest the appointment of a primary Auditor to conduct audit on his behalf and there upon such Primary Auditor shall audit the accounts in accordance with the directions and guidelines issued by the Comptroller and Auditor General.

34. Grants-in-Aid.—The Board may sanction grants-in-aid to the participating State Governments or the Union territory administration or the State Governments having a counter-magnet area and the local authorities, urban development authorities, housing boards and such other authorities of the State Government or the Union territory or other

State Government concerned as the case may be, for implementing the sub-regional plans and project plans or for developing the counter-magnet area.

35. Procedure for sanctioning grants-in-aid.—

(1)(a) Unless in any case the Board directs otherwise, every order sanctioning a grant shall indicate whether it is recurring or non-recurring in nature and specify clearly the object for which it is given and the conditions, if any, attached to the grant. In the case of non-recurring grants for specific objects, the order shall also specify the time limit within which the grant or each instalment of it is to be spent.

(b) An order for the payment of a grant-in-aid should be so worded that there is a specific direction for the payment of a specified sum and should be distinguishable from an order approving a proposal for a grant-in-aid.

(2)(a) Only so much of the grant shall be paid during any financial year as is likely to be expended during the year. In the case of grants for specific works or services such as buildings, water supply schemes and the like, payments should be authorised according to the needs of the work. It shall be ensured that money is not drawn in advance of requirements. A rush for payments of these grants in the month of March should be avoided.

(b) Where grant-in-aid involves one time payment it should be paid, as far as possible, before the end of December. In any case, rush towards payments of such grants in the last quarter of the financial year should be avoided.

(3) Before a grant is paid to any local authorities, urban development authorities, housing boards or such other authorities of the State Governments and Union territory administration, the Board shall invariably obtain the following set of audited statements of accounts of the authority concerned in order to see that grant-in-aid is justified by the financial position of the grantee and to ensure that previous grants, if any, was spent for the purpose for which it was intended :—

- (i) the receipt and payment accounts of the authority as a whole for the financial year;
- (ii) the income and expenditure accounts of the authority as a whole for the financial year; and
- (iii) the Balance Sheet, if any, as at the end of the financial year for the authority as a whole.

36. Certificate of utilisation.—In cases in which conditions are attached to the utilisation of grants sanctioned to local authorities, Urban development authorities, Housing boards and such other authorities of the State Government and the Union territory administration in the form of specification of particular objects of expenditure or the time within which money must be spent, or otherwise, the State Government and the Union territory administration shall be primarily responsible for certifying to the Board where necessary, the fulfilment of the conditions attaching to the grant.

37. Conditions of grant in aid.—(1) Unless it is otherwise ordered by the Board, every grant made for a specific object is subject to the implied conditions :—

- (i) that the grant shall be spent upon the object within a reasonable time, if no time-limit has been fixed by the Board;
- (ii) that any portion of the amount which is not ultimately required for expenditure upon that object shall be duly surrendered to the Board.

(2) In order to satisfy itself regarding the manner in which the affairs of the recipient body are managed and the grants are utilised, the Board may require the accounts of the body or authority in receipt of a grant-in-aid from the Board to be audited.

38. Loans.—The Board may sanction loans to the State Governments and the Union territory administration or to the local authorities, Urban development authority, Housing Boards or such other authorities of the State Governments or the Union territory, as the case may be, which are implementing the sub-regional plans and the project plans or developing a counter-magnet area.

39. Conditions of loan.—(1) All sanctions of loans shall specify the terms and conditions including the terms and conditions of repayment and payment of interest.

(2) The borrowers shall be required to adhere strictly to the terms settled for the loans made to them. Modifications of the terms in their favour can be made subsequently only for special reasons.

40. Calculation of interest.—(1) Interest shall be charged at such rate as may be specified by the Board for any particular loan or for the class of loans concerned and the rate of interest prescribed by the Government from time to time shall invariably be adopted by the Board.

(2) A loan shall bear interest for the day of payment but not for the day of repayment. Interest for any

shorter period than a complete year shall be calculated as :—

$$\frac{\text{No. of days} \times \text{Yearly rate of interest}}{365}$$

365

Unless any other method of calculation is specified by the Board in any particular case or class of cases.

41. Loan agreement.—In the case of loans to local authorities, urban development authorities, housing boards and such other authorities other than the State Governments and the Union territory administration, a loan agreement specifying all the terms and conditions shall be executed. A clause shall invariably be inserted in all such agreement enabling the Board at any time to call for accounts of the applicants relating to any accounting year with power to depute an officer specially authorised for this purpose to inspect the applicant's books, if necessary.

42. Security for loans.—Loans to Local authorities, urban development authorities, housing boards and such other authorities other than the State Governments and the Union territory administration shall be sanctioned only against adequate security. The security to be taken shall ordinarily be at least 33 1/3 per cent more than the amount of loan; provided that the Board may accept a State guarantee in lieu of the security.

43. State Government to certify.—(1) An order for the payment of a loan should be so worded that there is a specific direction for the payment of a specified sum and should be distinguishable from orders approving a proposal for loan.

(2) In cases where loans are sanctioned in favour of authorities, such as local authorities, urban development authorities, housing boards and such other authorities, other than the State Governments and the Union territory administration in which conditions are attached to the utilisation of loan, either in the shape of the specification of the particular objects on or the time within which the money must be spent or otherwise, the State Government and the Union territory administration shall be primarily responsible for certifying to the Board the fulfilment of the condition attaching to the loan.

44. Payment in instalments and moratorium.—When a loan is released in instalments, each instalment of the loan so drawn shall be treated as a separate loan for purposes of repayment of principal and payment of interest thereon except where the previous instalments drawn during a financial year are, for this purpose, allowed to be consolidated into a single loan as at the end of that particular financial

year. In the latter event, simple interest at the specified rate on the various loan instalments from the date of drawal of each instalment to the date of their consolidation shall be separately payable by the borrower. Repayment of each loan or the consolidated loan, as the case may be, and the payment of interest thereon shall be arranged by the borrower annually on or before the anniversary date of drawal or consolidation of the loan in such number of instalments as the Board may specify. The Board may allow, in deserving cases, a moratorium towards repayment of principal but not for the payment of interest. But should it appear that there is an undue delay on the part of the debtor in taking out the last instalment of a loan, the Board may at any time declare the loan closed and order repayment of capital to begin. The officer in charge of accounts of the Board shall bring to the notice of the Board any delay that appears to him to require this remedy and he shall take this step whether there are any dates fixed for taking of instalments or not.

45. Default in payment.—(1) The loan sanctions in all cases and the agreement in the case of local authorities, urban development authorities, housing boards and such other authorities should invariably include a provision for the levy of penal interest on over-due instalments of interest or principal and interest. The loan-sanctions and agreements in the case of local authorities, urban development authorities, housing boards and such other authorities of State Governments and Union territory administration should invariably stipulate a higher rate of interest and provide for lower rate of interest in the case of punctual payments. The penal or the higher rate of interest, as the case may be, shall not, except under special orders of the Board, be less than 2 1/2 per cent per annum above the normal rate of interest specified by the Board from time to time for the loans advanced.

(2) Any default in the payment of interest upon a loan or in the repayment of principal, shall be promptly reported by the officer in charge of accounts to the Board.

46. Accounts and control.—Subject to such general or specific directions as may be given by the Comptroller and Auditor General, detailed accounts of grants and loans given by the Board shall be maintained by the officer in charge of the accounts who shall also watch their recovery and see that the conditions attached to each loan are fulfilled.

47. Annual statement of loans and advances.—

(1) The officer in charge of accounts of the Board shall submit to the Board an annual statement showing the details of the outstanding loans borne on his

books under the Head "Loans and Advances by the Board". The statement shall be submitted in Form 'G'.

(2) The officer in charge of the accounts of the Board shall also submit to the Board an annual statement showing the details of the outstanding loans received by the Board under the Head "Loans and Advances received by the Board". The statement shall be submitted in Form 'H'.

CHAPTER VII MISCELLANEOUS

48. Form and time of submission of Annual Report.—The Annual Report in respect of the year last ended giving a true and full account of the activities of the Board during the previous financial year shall contain the particulars specified in Schedule II and shall be submitted to the Government by the 15th of May each year.

[No. K. 14011/15/84-NCR]

R.L. PARDEEP, Jt. Secy.

FORM A (See Rule 23)

NOTICE UNDER SUB-SECTION 1 OF SECTION 12 OF THE NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD ACT, 1985 READ WITH RULE 23 OF THE NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD RULES, 1985

Notice is hereby given that:—

(1) (a) The draft of the Regional Plan has been prepared; and

(b) A copy thereof will be available for inspection in the office of the National Capital Region Planning Board situated at _____ on all working days from 11 A.M. to 3 P.M. till the date mentioned in para 3 hereinafter.

(2) Objections and suggestions are hereby invited to the draft regional plan.

(3) Objections and suggestions may be sent in writing to the Member-Secretary, National Capital Region Planning Board at _____ before the _____ day of _____ 19____.

Any person making the objections or suggestions should also give his name and address.

MEMBER SECRETARY

Place : New Delhi

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING
BOARD

Dated :

FORM B

(See Rule 27)

Notice under Sub-section 1 of Section 13 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 read with Rule 27th of the National Capital Region Planning Board Rules, 1985

Notice is hereby given that:—

(1)(a) The final Regional Plan has been prepared; and

(b) A copy thereof will be available for inspection in the office of the National Capital Region Planning Board situated at—

on all working days from 11 A.M. to 3 P.M.

Place : New Delhi.

MEMBER SECRETAR

Dated :

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD.

FORM C

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

Detailed Budget Estimates for the year 19—

ADMINISTRATION (Expenditure)

(See Rule 28)

Statement showing the revised estimates 19— and budget estimates 19— vis-a-vis the actual expenditure

Objects of expenditure like salaries travel expenses, office expenses, etc.	Actual for the years			Sanctioned budget grant	Last seven months actuals	First five months actuals of current year 19—	Anticipated expenditure for the remaining seven months of the year 19—	Revised estimates for the year 19—	Proposed budget estimates for the year 19—	Reasons for variations between col. 5— col. 9 and 9-10.
	19—	19—	19—							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

FORM D

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD
ESTABLISHMENT

Statement of details of provision proposed for pay of officers/Establishment for the year 19— 19—

(See Rule 28)

Name and designation	Reference to page of estimate form	Sanctioned pay of the Minimum—maximum—actual pay of the person concerned due on 1st April next year			Amount of provision for the year at the rate in col 3(c)	Increment falling due within the year			Total provision for the year i.e. total of columns 4 and 4(c)	Remarks
		(a)	(b)	(c)		Date of increment (a)	Rate of increment (b)	Amount of increment for the year (c)		
1	2	3			4	5			6	7

FORM E
NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD
NOMINAL ROLLS
(See Rule 28)

R.E. 19—19—/B.E. 19—19

Name and designation	Pay	Dearness Allowance	City compensatory allowance	House Rent Allowance	Overtime Allowance	Children Educational allowance	Leave Travel Concession	Other allowance	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Total

FORM F
NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD
Abstract of Nominal Rolls
(See Rule 28)

Actual sanctioned strength as on 1-3-19—	Particulars of posts	Sanctioned Budget grant 19—19		Revised Estimates 19—19		Budget Estimate 19—19		Explanation for difference between sanctioned Budget Grant, Revised Estimate and budget estimates
		No. of posts included	Pay and allowances	No. of posts included	Pay and allowances	No. of posts included	Pay and allowances	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Officers							
	(a) Posts filled							
	(b) Posts vacant							
	Total—I Officers							
	II. Establishments							
	(a) Posts filled							
	(b) Posts vacant							
	III. Class IV							
	(a) Posts filled							
	(b) Posts vacant							
	Total—III Class IV							
	Grant total—I, II and III							

FORM G

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

Statement of Loan/Advances sanctioned to the Board

Financial year 19----

[See Rule 47 (1)]

Name of person/ party receiving the loan/ advance	Amount of loan/ advance sanctioned	Rate of interest	No and date of orders authorising the loan/ advances	Balance from last year	Amount advanced this year	Total	Repayment of principal				Payment of interest		
							Instalments of repayment during the year and arrears of instalments due relating to earlier years, if any (figures to be shown year-wise)	Amount of principal repaid during the year	Amount of defaults in repayments of principal (col. 8-9) (figures to be shown year-wise)	Balance of loans/ advances at the close of the year (Col. 7 & Col. 9)	Amount of interest due for and upto the year under review	Amount of interest received and credited to revenue during the year	Balance of interest unpaid
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Foot Note :

1. The amount of loan consolidated during the year shall also be indicated in Column 6.
2. Simple interest recovered in respect of individual instalments paid during the year may be indicated against the particular instalments in Column 13.

FORM H

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

Statement of loans/advances received by the Board—Financial year 19----

[See Rule 47(2)]

Name of person/ party receiving the loan/ advance	Amount of loan/ advance received	Rate of interest	No and date of orders authorising the loan/ advances	Balance from last year	Amount received during the year	Total	Repayment of principal				Payment of interest		
							Instalments of repayment during the year and arrears of instalments due relating to earlier years if any (figures to be shown year-wise)	Amount of principal repaid during the year	Amount of defaults in repayments of principal (Col. 8-9) (figures to be shown year-wise)	Balance of loans/ advances at the close of the year (Col. 7- Col. 9)	Amount of interest due for and upto the year under review	Amount of interest paid and credited to revenue during the year	Balance of interest unpaid
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

SCHEDULE I
NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD
BUDGET AND ACCOUNT HEADS

(See Rule 28)

ADMINISTRATION

HEAD OF ACCOUNTS (Expenditure)

1. Salaries
2. Wages
3. Travel Expenses
4. Office Expenses
 - (a) Furniture
 - (b) Postage
 - (c) Office Machine/Equipment
 - (d) Liveries
 - (e) Hot and cold weather charges
 - (f) Telephones
 - (g) Electricity and water charges
 - (h) Stationery
 - (i) Printing
 - (j) Staff car and other vehicles
 - (k) Other items
5. Fee and Honorarium
6. Payment for professional and special services
7. Rents, rates and taxes/royalty
8. Publications
9. Advertising, Sales and Publicity Expenses
10. Loans/Grants-in-Aids/Contributions/Subsidies.
11. Hospitality expenses/Sumptuary allowances, etc.
12. Write off/Losses
13. Suspenses
14. Other charges (A residuary head, this will also include regards and prizes)

HEADS OF ACCOUNT (Receipts)

1. Payment by Central Government
2. Fees
3. Fines and other receipts

SCHEDULE II
NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD
Form of annual report of the National Capital Region Planning Board
(See Rule 48)

Annual Report for the financial year April 19— March 19—

1. Introductory
2. Constitution of the Board including changes therein
3. Meetings of the Board
4. Constitution of the Planning Committee including changes therein
5. Meetings of the Planning Committee
6. Details of the activities in the various sub-regions
7. Details of activities in urban areas outside the National Capital Region selected under sub-section (f) of Section 8.

